Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 25-08-2005

Participants : Khanna Shri Avinash Rai

Title : Problems being faced by the farmers of border area of the country.

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर कांटेदार तार लगाई गई है। खास तौर से पंजाब का जो बार्डर है, वहां किसानों की जमीन तार के दोनों तरफ है। जब किसानों को अपनी जमीन पर काम करने जाना होता है तो वहां जाने के लिए दिन में दो दो घंटे का समय ही निश्चित है। इससे किसान अपनी खेती पूरी नहीं कर पाते क्योंकि न तो बॉर्डर पर 24 घंटे बिजली मिलती है और जो नहर का पानी छोड़ा जाता है, वह भी कभी कभी रात को छोड़ा जाता है। इसलिए

किसानों को खेती करने में मुश्किल होती है। मेरा सरकार से आग्रह है कि किसानों के आने जाने के लिए जो गेट है, वह सुबह से शाम तक खोला जाए।

उपाध्यक्ष जी, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां जो महिलाएं खेती या मज़दूरी करने के लिए जाती हैं, उनकी चैकिंग के लिए वहां कोई महिला कर्मचारी नहीं है। पुरुषों की हाजिरी में पुरुष ही महिलाओं की चैकिंग करते हैं। इसलिए वहां महिलाओं द्वारा चैकिंग का इंतजाम भी कराया जाना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पंजाब में खेती की कटाई कंबाइन्स से होती है। जो बड़े कंबाइन्स हैं, वे भी बॉर्डर के बाहर नहीं जा सकते। एक बात और बॉर्डर के एरिया में है कि वहां न स्कूलों में टीचर जाते हैं और न ही अस्पतालों में डाक्टर जाते हैं। इस कारण बॉर्डर के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेरी सरकार से विनती है कि बॉर्डर एरिया डैवलपमैंट बोर्ड बनाएँ ताकि बॉर्डर के लोगों की समस्याओं को अलग ढंग से देखा VÉÉA[h25] ,ताकि बार्डर के लोगों की समस्याओं को अलग ढंग से देखा जाए।

14.00 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और गंभीर मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं। बार्डर पर माइंस वगैरह बिछाई गई हैं और उसके लिए सरकार को मुआवजा देना होता है, लेकिन किसानों को मुआवजा देने में देरी हो रही है। जिन किसानों की जमीन में माइंस बिछाई गई हैं और जो जमीनें तार के नीचे आई हैं, उन किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिल रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरपंचों, वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स और वहां के प्रशासन की मीटिंग होती थी, लेकिन यह मीटिंग न होने के कारण समस्याएं बढ़ रही हैं।

मेरा सरकार से निवेदन है कि यह मीटिंग नियमित रूप से हो, जिससे कि बार्डर के पास रहने वाले लोगों की समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाया जा सके।